

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.56  
21 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय वस्त्र नीति

56. श्री जयदेव गल्ला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की कोई एक व्यापक वस्त्र नीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और विज़िन दस्तावेज क्या है;
- (ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र नीति पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि वर्ष 2005 में बहु-रेशा समझौता समाप्त किए जाने के बावजूद भी वस्त्र निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है और कम होकर 12 प्रतिशत पर आ गयी है जो वर्ष 1996 के निर्यात का आधा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़बिन इरानी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- i. लोगों की बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकार्य मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े का उत्पादन करना।
- ii. निरंतर संपोषणीय रोजगार के प्रावधान और देश के आर्थिक विकास में योगदान करना; और
- iii. विश्व बाजार में हिस्सेदारी की वृद्धि करने के लिए आत्म विश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करना।

एनटीपी 2000 के प्रबलित क्षेत्र हैं; रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, कच्ची सामग्री के आधार का सशक्तिकरण, उत्पाद विविधीकरण और निर्यात में वृद्धि।

(ग): 2005 में मल्टी फाइबर करार के समाप्त होने के बाद भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात वर्ष 2005-2006 में 17.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से 5.7 सीएजीआर बढ़कर वर्ष 2018-19 में 36.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*